हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 23 जुलाई 2026, समय 13:05 (5 मिनट)

==========

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाएगी। आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, श्री मोदी ने यह घोषणा करते हुए फिर कहा कि देश के युवाओं की भलाई और उनके भविष्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस मामले में सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जो लोग युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे कई कदमों के तहत लिया गया है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप-प्रत्यारोप करने और बार-बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।

(यह गंभीर मसला है हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है, वह पार्लियामेंट और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियां में हम जाएं हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय ना हो।)

श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया।

उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दें से राजनीतिक फायठा उठाना चाहते है।

आज देश भर में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन, 23 जुलाई 1927 को मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। साल 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, जिसे 1956 में 'आकाशवाणी' नाम दिया गया।

आज़ादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण के सफर तक, रेडियो ने देश के विकास, शिक्षा के प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में अहम भूमिका निभाई है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कृषि और साक्षरता के प्रति जागरूकता फैलाने में इसका योगदान अतुलनीय है।

'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' के ध्येय वाक्य के साथ, आज के इस डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी अटूट विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का सबसे भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे न्यायिक अधिकारियों की सेवा मुक्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने पर विचार करें। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने यह निर्देश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए जिसमें जिला न्यायपालिका के जजों की सेवा मुक्ति की आयु 62 साल करने की मांग की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश इस मुद्दे पर संबंधित उच्च न्यायालय से सलाह-मशविरा करके कोई फैसला लें। अगर वे सहमत होते हैं, तो ऐसे राज्यों में न्यायिक अधिकारियों को 61 साल की उम्र तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी। यह प्रावधान 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।

हरियाणा युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग द्वारा कल पंचकूला में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने की।

कार्यशाला में श्री राजीव रंजन ने बताया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवाओं को देश की शीर्ष 2,000 कंपनियों में छह से नौ माह की अवधि के लिए इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध कराया जाता है।उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक इंटर्न को प्रतिमाह 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें कार्यस्थल पर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के साथ-साथ प्रतिष्ठित कंपनियों में नियमित रोजगार प्राप्त करने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं।

==========